

Fourteenth Loksabha**Session : 4****Date : 22-03-2005****Participants : Patel Shri Dahya Bhai V.**

>

Title: Issues relating to proposed corporation/privatization of the Electricity Department of Union Territory of Daman and Diu.

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : अध्यक्ष महोदय, दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में बिजली के प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज की बात चल रही है। लेकिन दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में बिजली से हम हर साल 240 करोड़ रुपये का लाभ कमा कर केन्द्र सरकार को देते हैं। दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में इलैक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज की प्रेजेंटेशन करने के लिए गृह मंत्रालय और दमन प्रशासन को क्या जरूरत है ? दमन प्रशासन ने बिजली को प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज करने के लिए पावर ग्रिड कम्पनी को 70 लाख रुपया कंसल्टिंग चार्ज दिया है। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार जो कम्पनीज प्रॉफिट देती हैं, उनको प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हर साल 240 करोड़ रुपये लाभ कमाते हैं। जब अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में बिजली को प्राइवेटाइज और कार्पोरेटाइज नहीं किया गया है तो दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली में इसको प्राइवेटाइज करने की क्या आवश्यकता है ? गृह मंत्रालय और दमन प्रशासन इलैक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करने के पीछे पड़े हैं लेकिन दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली की आम जनता, लेबर क्लास, सारे राजनैतिक और कर्माचारी संगठन, उद्योगपति, जन प्रतिनिधि ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have made your point very clear.

श्री दह्याभाई वल्लभभाई : मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस प्रस्ताव को तुरंत रद्द किया जाये तथा इस संबंध में दमन प्रशासन को सीधा आदेश जारी किया जाये ताकि इस संघ शासित प्रदेश की आम जनता राहत की सांस ले सके। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: I am appealing to all the hon. Members to be very brief. I have already given chance to 21 hon. Members. Every hon. Member wants to speak. If you cooperate with one another, then we can give opportunity to many Members.